

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—४१० / २०१९

नवल किशोर सिंह चौधरी और अन्य याचिकाकर्ता
बनाम
झारखण्ड राज्य और अन्य उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री जे०एफ० टोप्पो, ए०पी०पी०; श्री डी०के० मालतियार,
अधिवक्ता; श्री अमित किस्कु, अधिवक्ता; श्री कृष्णा मुरारी,
अधिवक्ता

आदेश सं० ०३: दिनांक: २६वीं जून, २०२०

आनंदा सेन, न्याया० के अनुसार

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उन्हें ऑडियो और वीडियो की स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।
- वर्तमान याचिका को इसकी मूल फाइल डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० ६४५७ / २०१६ की बहाली के लिए दायर किया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक १६.०१.२०१९

के अनुलंघनीय आदेश का पालन नहीं करने के कारण दिनांक 23.01.2019 को खारिज कर दिया गया।

3. याचियों के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि नई टाइप की गई प्रतियां दाखिल की गई थीं, लेकिन त्रुटि संख्या—4 को छोड़कर अन्य सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। वह निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता यह अभिवचन करता है कि उब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6457 / 2016 को इसकी मूल फाइल में बहाल करने के तुरंत बाद त्रुटि संख्या 4 को हटा दिया जाएगा।

4. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है।

5. याचियों की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, सी०एम०पी० को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि रिट याचिका (एस) सं० 6457 / 2016 में जो त्रुटि रह गया है उसे तीन सप्ताह के भीतर अवश्य ही हटा दिया जाना चाहिए।

(आनंदा सेन, न्याया०)